Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged use of political power to suppress freedom of speech.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, हम सभी लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम गर्व के साथ बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र संविधान के तहत चल रहा है और सभी को बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और भाषण देने का भी अधिकार है। आर्टिकल 19 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मूलभूत अधिकार दिया गया है। …(व्यवधान) ठीक है, आप हमारे पास आकर पूछिए । उसका कर्नाटक में उत्तर देंगे । …(व्यवधान) लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इस सरकार के पिछले कुछ वर्षों में मीडिया पर पाबन्दी लगाने के कई किस्से हो चुके हैं। खासकर जब भी मीडिया में सरकार के विचार के खिलाफ या रियलिटी चेक जैसी चीजें आती हैं, तब उसको डराने, धमकाने और उनका मुंह बन्द करने का काम हो रहा है। मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा । …(व्यवधान) दो दिन पहले ही एबीपी न्यूज के दो ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया । उनमें से मिलिन्द खाण्डेकर उस न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे और 14 साल से उस चैनल के साथ काम कर रहे थे । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसमें हम क्या कर सकते हैं, वह एक प्राइवेट चैनल है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उनके साथ ही दो एंकर्स भी काम कर रहे थे । उनकी एक ही गलती थी कि प्रधानमंत्री जी 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने विचार कहते हैं, उन विचारों की रियलिटी चेक करने के लिए एंकर ने छत्तीसगढ़ में अपने रिपोर्टर को भेजा । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? वह प्राइवेट चैनल है, उनका प्राइवेट डिसीजन है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उसमें एक महिला की आमदनी डबल हुई है, ऐसा उन्होंने कहा था । उस महिला के पास जाकर उस रिपोर्टर ने पूछा तो उस महिला ने कहा कि यह गलत है और मुझे सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपकी आमदनी डबल हो गई है, क्योंकि यहां पर पैडी की क्रॉप हम दे रहे हैं।...(व्यवधान) यह न्यूज आने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर ऐसा दबाव डाला गया, एबीपी चैनल पर भी दबाव डाला गया और आखिर में मैनेजमेंट को यह तय करना पड़ा कि मुझे एबीपी चैनल चलाना है। इन इम्प्लाइज को लेकर मैं क्या करूंगा, इसलिए उन तीनों इम्प्लाइज को निकाल दिया गया।...(व्यवधान) इस तरह से उनका मुंह बन्द करने की कोशिश हो रही है।...(व्यवधान) दूसरी तरफ और एक बात हो रही है।...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, आईएंडबी मिनिस्टर जी इसके बारे में रिस्पांड करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : मगर यह प्राइवेट चैनल की बात है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यहां सेंट्रल हाल में एक सीनियर एमपी, राज्य सभा के मेंबर हैं, वह खुद मीडिया को चैलेंज करते हैं कि अगर हमारे विचारों पर आप नहीं चलेंगे ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। ऐसी बातें मत कहिए ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम आपका चैनल बन्द करा देंगे ।...(व्यवधान) उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। एनडीटीवी के ऊपर...(व्यवधान) आपको मालूम है कि नेशनल टीवी को भी उन्होंने 24 घण्टे बन्द करवाया था और दूसरों को भी ऐसा ही कहते हैं। ...(व्यवधान) अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो हम कहां बात करेंगे? ...(व्यवधान) हम अपनी बात आपके ही सामने रख सकते हैं।...(व्यवधान) यह रोज क्यों हो रहा है? अगर आप चैनल को बन्द करना चाहते हैं, प्रेस को भी दबाना चाहते हैं, जो आपके विचारों के खिलाफ लिखना चाहते हैं, उनको भी दबाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात आ गई है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह अच्छी बात नहीं है। जो आप ऐसी विचारधारा पर चल रहे हैं, वह गलत है। जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, वह ठीक नहीं है और फण्डामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए ।

मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि ऐसा न हो ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री {कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त)}: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में एक सिलसिला आजकल देखने को मिलता है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो देश में कोई भी बात हो, उसके लिए अपोजीशन सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूं और माननीय खड़गे जी में अगर हिम्मत हो तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लें क्योंकि उन्होंने बात रखी है और मैंने सुना है।

आज ये जिस चैनल की बात कर रहे हैं, उसने जो सबसे पहली खबर चलाई थी, वह गलत खबर चलाई थी । उसके बावजूद भी सरकार ने कोई शो-कॉज- नोटिस चैनल को नहीं दिया। यह चैनल फ्रीडिश के ऊपर चलता है और फ्रीडिश के ऊपर सबसे ज्यादा टी.आर.पी. आती है। फ्रीडिश सरकार की है और फ्रीडिश के ऊपर बिना किसी इंटरप्शंस के यह लगातार चल रहा है। अगर सरकार को कुछ उसमें दखलंदाजी करनी होती तो फ्रीडिश के अंदर करती । सरकार का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं, उसकी टी.आर.पी लगातार गिर रही है क्योंकि लोग उसको देखना नहीं चाहते । अब उसका जिम्मा ये सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। ये वही चैनल है जो पूरे देश में अपोजीशन फैलाने की कोशिश कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : अब मुझे इसे पूरा करने दो और मैं बताना चाहूंगी कि आज लंच ऑवर नहीं है। आज कंटिनुएशन में बिल लेना है। अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा ।

...(व्यवधान)